International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 6.972 Volume 10, Issue 12, Dec 2023
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

हरियाणा के भिवानी जिले के संदर्भ में मानव विकास और जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में संबंध

शोधार्थी
सुरेश कुमार
(भूगोल विभाग)

शोध निर्देशक
डॉ. राजू शर्मा
(भूगोल विभाग)

शोध केन्द्र : श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान

लेख सार :

वास्तव में आधुनिक संकटकाल में यह भुला दिया गया है कि ''मनुष्य ही राष्ट्र की वास्तविक संपदा है।'' इस कारण वे भौतिक संपदा के साथ मानवीय हितों का मूल्यांकन करने की गलती करते हैं। यह भी प्रमाणिक है कि धन के बिना मानव कल्याण संभव नहीं हैय लेकिन सुधार का सबसे पहला पैमाना मानव जीवन का प्रथम श्रेणी (गुणवत्ता) है। धन ही अवसरों के समाधान की अनुमति देता है। मानव विकास का आवश्यक लक्ष्य मानव के लिए सुलभ अवसरों की सीमा का विस्तार करना है ताकि सुधार अधिक लोकतांत्रिक और भागीदारीपूर्ण हो जाए। इन सही अवसरों में स्वस्थ्य, दीर्घ जीवन की संभावनाएँ, शिक्षित होने के अवसर और सभ्य जीवन जीने के अवसर शामिल हैं। अभिनव और उत्पादक होने और आत्म–सम्मान के अस्तित्व का नेतृत्व करने के अवसरों के साथ–साथ कई अलग–अलग विकल्प हैं।

लेख शब्द : मानव विकास, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, सहायक, बाधक, उत्पादन, सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, नियोजित, संतुलन, नियंत्रण, स्थिरता, गतिशीलता।

1. प्रस्तावना :

मानव विकास एक विशाल अवधारणा है। मानव विकास, मानव सुधार की अवधारणा से संबंधित है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के लोगों के लिए सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक शर्तें तैयार करना है। मानव विकास सूचकांक (HDI) एक समग्र सूचकांक है जो मानव अस्तित्व के कई आयामों के साथ–साथ दीर्घायु, सूचना और गरिमापूर्ण जीवन के मात्रात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) 'मानव कल्याण' में विकास के मार्ग को मापने के लिए एक व्यापक रूप से स्थापित मापक है। जबकि उपलब्धियों का स्तर मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, अभाव का स्तर मानव गरीबी सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। 2018 में भारत 0.640 के मध्यम स्तर मानव विकास सूचकांक के साथ दुनिया के 189 देशों में 130वें स्थान पर रहा। 2021 में भारत का 0.633 के मध्यम स्तर मानव विकास सूचकांक के साथ दुनिया के 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है।

हरियाणा की पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2002 में जारी की गयी थी। इसका मूल विषय वैश्वीकरण की तकनीक में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना था। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ और दीर्घ जीवन,

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

जीवन जीने की क्षमता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल देशव्यापी लाभ को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मानव दक्षता में वृद्धि के तहत देश भर में प्रति व्यक्ति सकल लाभ कुछ आयामों से अधिक समय तक बिना देरी के। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार लगातार मानव विकास के विविध आयामों को साकार करने का प्रयास कर रही है।

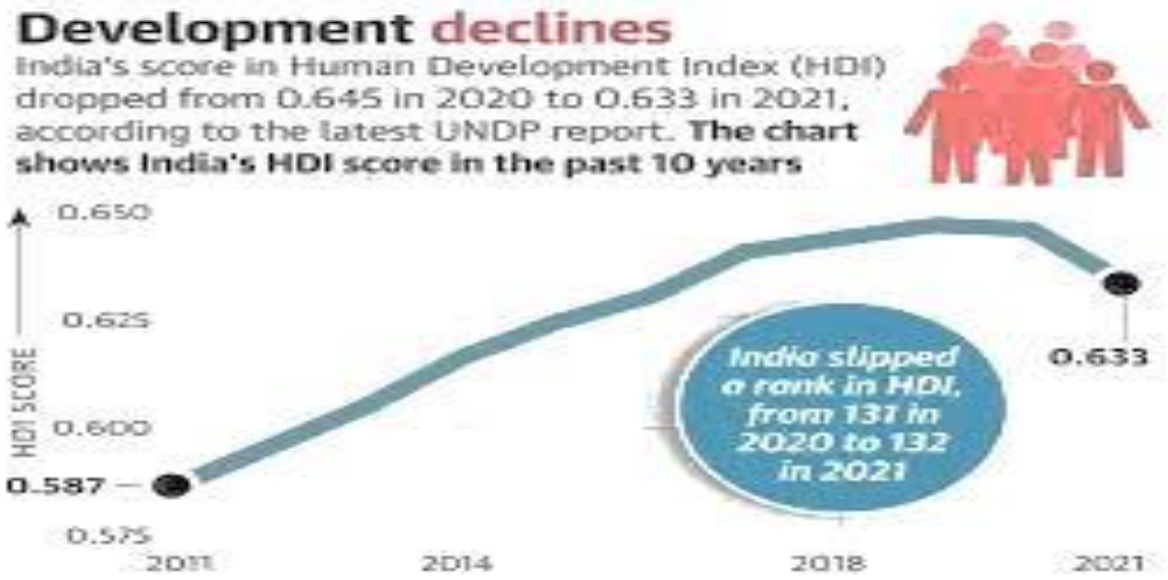

मानव सुधार (विकास) की अवधारणा मानव संसाधन विकास के विचार से अधिक पूर्ण है। यह विकास का नया विचार है जो 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा अपनी विकास रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था।

इस रिपोर्ट में महबू–उल–हक ने लिखा है कि ''मानव सुधार का लक्ष्य ऐसा मजबूत माहौल तैयार करना है, जिसमें लोग लंबे समय तक स्वस्थ और रचनात्मक जीवन का लुत्फ उठा सकें.''

हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में मानव विकास रणनीति मानव को सुधार एजेंडे के केंद्र में रखती है, जबकि वित्तीय विकास और समृद्धि को विकास की क्षमता के रूप में मानते हैं और अंत के रूप में नहीं। मानव विकास रणनीति का मूल विचार यह है कि विकास का उद्देश्य मानव जीवन में सुधार करना है, न केवल बढ़ती आय के माध्यम से, बल्कि उन चीजों की सीमा को बढ़ाकर जो एक व्यक्ति करना चाहता है और कर सकता है, जैसे कि स्वस्थ और स्वस्थ रहना उचित पोषण, ज्ञान प्राप्त करना और सामुदायिक भागीदारी। मानव विकास का विचार उन्नीस सौ अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में पूरी तरह से डॉ. अमर्त्य सेन और डॉ. महबूब–उल–हक के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था। मानव विकास सूचकांक (HDI) एक समग्र सूचकांक है जो मानव जीवन के विभिन्न आयामों के साथ–साथ दीर्घायु, विशेषज्ञता और गरिमापूर्ण जीवन के मात्रात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) और मानव गरीबी सूचकांक (HDI) 'मानव कल्याण' में प्रगति की दिशा को मापने के लिए व्यापक रूप से नियमित मापक हैं। जबकि उपलब्धियों के चरण को मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, अभाव के चरण को मानव गरीबी सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है।

पूर्ण मानव विकास सूचकांक (HDI) मानव सुधार के तीन सरल आयामों का एक एकीकृत संकेतक है –

1. शुरुआत में जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

2. शिक्षण के औसत और अनुमानित वर्ष ज्ञान एकत्र करने की क्षमता को दर्शाते हैं।

3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सभ्य जीवन जीने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

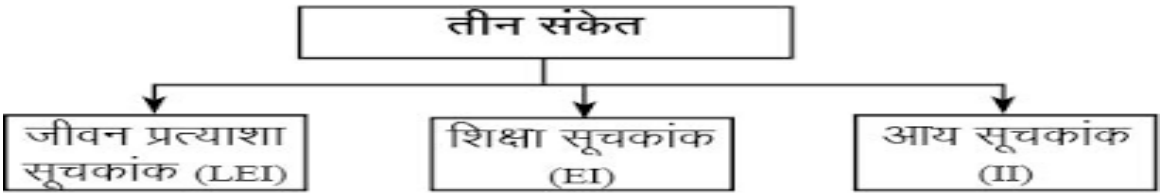

2. मानव विकास का महत्व

किसी क्षेत्र का आर्थिक और मानव विकास उस क्षेत्र में सुलभ मानव पूंजी के संचय की उपलब्धता और शुल्क पर निर्भर करता है। प्रदेशों के निर्माण में नियोजित आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में मानव विकास पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में विकास के वांछित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते और वहां विकास की दर कम रहती है। आज, अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस वास्तविकता को तरजीह दे रहे हैं कि मानव पूंजी में अधिक से अधिक वित्त पोषण किया जाए, ताकि वित्तीय विकास के साथ–साथ मानव संसाधन, जो मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, में अनुकूल विकास किया जा सके। किसी भी राज्य की जनसंख्या का जितना बड़ा भाग शिक्षित, कुशल और प्रशिक्षित होगा, रोजगार में लगा होगा, उतनी ही तेजी से उस राज्य का विकास होगा। मानव विकास की दृष्टि से भौतिक पूँजी की अपेक्षा मानव पूँजी को अधिक आवश्यक माना जाता है क्योंकि मानव संसाधनों की कार्यक्षमता और प्रभावोत्पादकता पर ही आर्थिक सुधार की शक्ल का निर्माण किया जा सकता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का भी एक बार मत था कि ''सबसे मूल्यवान पूंजी वह है जो मनुष्य में विनियोजित की जाती है''।

3. मानव विकास के आयाम

देश के हरियाणा राज्य के बारे में सरकार सीधे मानव विकास के कई आयामों के लिए मानव कौशल को बढ़ाती है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की क्षमता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल देशव्यापी आय में सुधार और वृद्धि शामिल है, साथ ही साथ मानव विकास। मानव सुरक्षा और अधिकारों, लैंगिक समानता, आर्थिक वृद्धि के साथ राजनीतिक और सामुदायिक भागीदारी के लिए मानव सुधार और सतत विकास के लिए पूर्वापेक्षाओं का निर्माण। सरकार की सहायता से इन क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ बुनियादी ढांचे के विकास से वित्त पोषण दक्षता में वृद्धि होगी, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी और रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण विकास और जीवन की संतुष्टि में सुधार होगा।

जनसंख्या वृद्धि : आर्थिक और मानव विकास में बाधा

(1) अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति :

विकसित क्षेत्रों की तुलना में अविकसित अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से विशिष्ट उदाहरणों में हैं। ये क्षेत्र गरीब, पूंजी–दुर्लभ और श्रम प्रधान हैं। पूँजी निर्माण की समस्या इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। अतः

पूँजी के अभाव तथा जनसंख्या के दबाव के कारण असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जो मौद्रिक विकास में मूलभूत बाधक है।

(2) खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या :

अविकसित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्यान्न की कमी की समस्या को और बढ़ा देती है। यह परेशानी तीन तरह से आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। सबसे पहले, खाद्यान्न की अपर्याप्त आपूर्ति से जनसंख्या का अल्पपोषण होता है, जिससे दक्षता और विनिर्माण क्षमता में कमी आती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और गरीबी होती है। दूसरे, खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों से अनाज आदि का आयात करना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन पर अधिक दबाव पड़ने से स्थान की विनिमय आपदा बढ़ जाती है। तीसरा, विदेशी विकल्प के लागू उपयोग की कमी जनसंख्या के अत्यधिक तनाव का 0.33 पहलू प्रभाव है।

(3) प्रति व्यक्ति आय पर नीचे की ओर परिणाम :

सूक्ष्म स्तर पर, प्रति व्यक्ति आय एक क्षेत्र के मानव सुधार (जीवन स्तर) को रेखांकित करने के लिए एक सूचकांक के रूप में कार्य करती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का भी प्रति व्यक्ति आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित स्तर तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है लेकिन उसके बाद अनिवार्य रूप से इसे कम कर देती है।

(4) पूंजी निर्माण का अभाव :

प्रो. स्पैंगलर के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्येक 3 श्रमिकों पर दो आश्रित हैं, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में यह अनुपात 3 : 4 है। आश्रितों का यह अत्यधिक प्रतिशत बचत करने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे पूंजी निर्माण कम हो जाता है। फिर, इन क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर अत्यधिक है जिसके कारण उनके पोषण पर संसाधनों की भारी बर्बादी होती है।

(5) कम व्यापक रहन–सहन :

मानव विकास की प्रक्रिया को तेज कर रहने के फैशन को बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन शिक्षित क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है, निर्माण में कमी आ रही है। अनाज, बुनियादी उद्योगों की कमी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, बेरोजगारी की समस्या जैसी मौजूदा कठिनाइयों के कारण आज भी लोगों का सामान्य आवास निम्न बना हुआ है।

(6) बेरोजगारी में वृद्धि :

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे बेरोजगारी के अवसर बढ़ जाते हैं। यदि अल्प–रोजगार अविकसित एवं विकासशील भागों में प्राथमिक लक्षण है तो अदृश्य (छिपी हुई) बेरोजगारी, कुशल बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी इन क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याएँ हैं। बेरोजगारी की ये पूर्वापेक्षाएँ कुपोषण, गरीबी और अविकसित क्षेत्रों में गिरावट को बढ़ावा देती हैं।

(7) असंतुलित विकास :

सीखने की जगह में तेजी से जनसंख्या वृद्धि असंतुलित तरीके से अलग–अलग घटकों के विकास की ओर ले जाती है क्योंकि इस तथ्य के कारण अधिकांश आबादी को बाद में कृषि क्षेत्र में खिलाया जाना है। चूंकि अविकसित क्षेत्रों में पूंजी संसाधनों की कमी है, इसलिए विनिर्माण उद्योगों में इस अतिरिक्त जनसंख्या उछाल को खाना अब व्यवहार्य नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि में वृद्धि और उत्पादकता में कमी और कृषि में प्रति व्यक्ति लाभ, ज्ञान का विकास स्थान के बारे में बाधा है। इसे अवरुद्ध और असंतुलित बनाता है।

क्षेत्र की खोज में भोजन, वस्त्र और शरण वहाँ के निवासियों की प्रमुख इच्छाएँ मानी जाती हैं और इनमें से किसी का भी अभाव या अभाव क्षेत्र की समूची आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उपरोक्त आवश्यकताओं के आकलन में, भोजन मौद्रिक विकास की सबसे तेज क्षमता है, क्योंकि संपत्ति के गुणात्मक वृद्धि के प्रभाव के कारण मनुष्य बहुत कम भोजन के साथ भी कहानी कहने के लिए जीवित रह सकता है और देश व्यापी संरचना पर एक तरह के तरीकों से सुधार के कार्यों के साथ जनसंख्या का प्रभावी विकास। एक प्रभाव है जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक विकास में गिरावट आती है क्योंकि यदि अध्ययन क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में प्रथम श्रेणी के भोजन के साथ काम नहीं किया जाता है, तो यह वहां के निवासियों और उसके समाज पर प्रभाव। यह मनुष्यों की बौद्धिक और मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है क्योंकि निवासियों की कार्य शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इसका असर क्षेत्र के कृषि, उद्योग, उत्पादन और प्रबंध की प्रक्रिया पर एक तरह से देखने को मिल रहा है।

जनसंख्या वृद्धि : आर्थिक विकास में सहायक

देश/प्रदेश में बढ़ती आबादी बाजारों को बढ़ा रही है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप विनिर्माण और रोजगार में वृद्धि होने लगी है। अतः जनसंख्या वृद्धि किसी प्रदेश के मानव विकास को प्रोत्साहित करती है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं–

(1) श्रम–शक्ति–पूर्ति का स्रोत :

मानव विकास प्राकृतिक संसाधनों, श्रम–शक्ति, पूंजी और प्रौद्योगिकी का अंतिम परिणाम है। इनमें से श्रम शक्ति सबसे आवश्यक तत्व है क्योंकि विकास की प्रक्रिया में यह एकमात्र गतिशील साधन है।

इमन कुजनेट्स के अनुसार, ''अन्य चीजें समान होने पर, जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि श्रम शक्ति को बढ़ाती है। क्षेत्र की कार्यशील श्रम शक्ति विकास की सबसे आवश्यक और ऊर्जावान चीज है और इस श्रम शक्ति का स्रोत जनसंख्या है।'' कार्यशील श्रम बल की आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में, जनसंख्या वृद्धि वित्तीय विकास का उत्प्रेरक है और अंत में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है।

(2) बाजारों का विस्तार :

आबादी में विस्तार से आसपास के तत्वों के श्रम बल के बारे में पता चलता है। इस दृष्टि से श्रम उत्पादक तो है ही, जनसंख्या में वृद्धि से उपभोग में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या आर्थिक विकास की क्षमता के

साथ–साथ साध्य भी है, अर्थात मनुष्य न केवल धन का उत्पादक है बल्कि धन का उपभोक्ता भी है। पूरकता के इस अनुभव में, जनसंख्या में उछाल उपभोक्ताओं के रूप में वस्तुओं की मांग पैदा करता है। जनसंख्या में उछाल वस्तुओं की अतिरिक्त माँग पैदा करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।

(3) उत्पादन में वृद्धि :

यदि क्षेत्र के अध्ययन की जनसंख्या वृद्धि 1 प्रतिशत वार्षिक या उससे कम है, तो जनसंख्या में यह धीमा परिवर्तन उत्पादन और विकास की दृष्टि से सहायक होता है, लेकिन यदि यह विकल्प 2 प्रतिशत या अधिक वार्षिक है, तो यह जनसंख्या में तेजी से है। विकास उत्पादन और विकास के मामले में एक बाधा है।

(4) पूँजी निर्माण के स्रोत :

राग्नार नर्क्से के अनुसार, अधिशेष श्रम दबाव एक प्रकार की अदृश्य बचत है और इन अदृश्य प्रबंधनीय बचतों को अल्प–रोजगार के रूप में पूंजी निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्र के अध्ययन में शारीरिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के निर्माण पर निर्भर करता है और मानव पूंजी का निर्माण शिक्षित और जानकार श्रम शक्ति पर निर्भर करता है।

(5) कौशल–निर्माण को बढ़ावा :

साइमन कुजनेट्स के अनुसार, 'मौद्रिक उत्पादन में उछाल परीक्षित ज्ञान की दुकान की एक विशेषता है।' नवीन तकनीकी की खोज एवं विकास मानव द्वारा किया जाता है, जो कि जनसंख्या का ही परिणाम है। जनसंख्या रचनात्मक दिमाग पैदा करती है, जो कौशल–निर्माण को गति प्रदान करती है, नई विशेषज्ञता की सूची में वृद्धि करेगी और इस कारण देशव्यापी उत्पादन में वृद्धि होगी।

अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश के हरियाणा राज्य में कृषि गतिविधियों की प्रधानता है तथापि इस गतिविधि के वांछनीय विकास में कृषि का कम उत्पादन कार्य, भूमि का असंतुलित वितरण, जनसंख्या पर निरंतर बढ़ता दबाव, सामान्य कृषि का दृष्टिकोण, आधुनिक बीज, उपकरण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में ढिलाई, सिंचाई की उपयुक्त क्षमता की कमी, अनियोजित संयुक्त फसल नमूना और स्थानीय कृषि की विशेषज्ञता, खेतों का छोटा आकार और खंडित रूप, फसल के कार्यान्वयन में ढिलाई आधुनिक कृषि कवरेज में बीमा योजना और क्षेत्रीय अशिक्षित और अज्ञानी किसान अब कृषि को एक प्रणाली के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि इसे मात्र निर्वाह या आजीविका की एक आवश्यक क्षमता के रूप में देखते हैं। अतः बहुफसली प्रणाली में कृषि के विशिष्ट सुधार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की क्षमता में आदर्श सुधार किया जाना चाहिए, हालांकि यह तभी संभव है जब कुओं, तालाबों, नलकूपों की संख्या और नहरों की लंबाई अधिक हो जाए। उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर समय और बीच में नहरों के कटाव को रोकने के लिए उपयुक्त तैयारी और पुख्ता कार्य किया जाए। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित राशि का व्यय एवं सदुपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में हरी खाद एवं गोबर का प्रयोग अति आवश्यक है। यहां हाथ में कृषि सेवाओं की नींव पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है। अध्ययन क्षेत्र में आज भी क्रान्तिकारी बीजों का अभाव है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता की तीव्रता के अनुसार किया जाना चाहिए। रबी, खरीफ और

जायद के आसपास के प्रमुख व्यवसाय और अनाज की फसलें आलू, शकरकंद, एक प्रकार की सब्जियां, सूरजमुखी, गेहूं आदि का निर्माण करती हैं, जिससे भोजन की गुणात्मक कमी पूरी हो जाएगी और क्षेत्र के निवासी अधिक उपज को बढ़ावा देने के माध्यम से प्राप्त धन से अपना जीवन यापन करने की स्थिति में होंगे।

CHART 2

Ranking of Indian states in the world according to 2015 Human Development Report

INDIAN STATES			COMPARABLE COUNTRIES	
States	Constructed HDI score	Hypothetical HDI ranks	Countries	HDI score
Kerala	0.7117	104	Maldives	0.706
Himachal Pradesh	0.6701	116	Uzbekistan	0.675
Tamil Nadu	0.6663	118	Philippines	0.668
Maharashtra	0.6659	119	South Africa	0.666
Punjab	0.6614	124	Bolivia	0.662
Haryana	0.6613	125	Kyrgyzstan	0.655
Jammu and Kashmir	0.6489	128	Iraq	0.654
Karnataka	0.6176	137	Tajikistan	0.624
Andhra Pradesh	0.6165	138	Tajikistan	0.624
Gujarat	0.6164	139	Honduras	0.606
ALL INDIA	0.6087			
West Bengal	0.6042	142	Bhutan	0.605
Rajasthan	0.5768	151	Ghana	0.579
Odisha	0.5567	154	Bangladesh	0.57
Madhya Pradesh	0.5567	155	Bangladesh	0.57
Assam	0.5555	156	Cambodia	0.555
Uttar Pradesh	0.5415	161	Pakistan	0.538
Bihar	0.5361	163	Myanmar	0.536

Sources: UNDP 2015 Human Development Report; RBI (for state per capita income); Desai, Sonalde, and Reeve Vanneman. India Human Development Survey-II, 2011-12 (for education indicators); SRS Based Life Tables 2009-13 and Mint calculations

2015 में भारत के हरियाणा राज्य का देश में मानव विकास सूचकांक कोटी में 0.6613 के साथ 125 स्थान था।

4. अनुसंधान क्षेत्र के मानव विकास में भविष्य में सुधार की रणनीति

सामाजिक, जनसांख्यिकीय और मानव विकास के सपनों को साकार करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है –

1. प्रदेश के बारे में पता लगाने में परिवार नियोजन और पैकेजों का विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन।
2. प्रदेश के गांव, तहसील और जिला स्तर पर सेवाओं की एकीकृत उपलब्धि।
3. प्रदेश में बेहतर बाल कल्याण सुविधाओं की उपलब्धता।

4. हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में झुग्गीवासियों, आदिवासी समुदाय, पहाड़ी आबादी और विस्थापित और पलायन करने वाली आबादी के लिए इस तरह के दृष्टिकोण का संचालन करना ताकि बच्चों को नियोजित किया जा सके और उनका पालन–पोषण किया जा सके।

5. भिवानी जिले में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों का आयोजन और उन्हें पूरा करना।

6. अनुसंधान क्षेत्र में गैर–सरकारी कंपनियों और गैर–सार्वजनिक तिमाही के साथ बेहतर समन्वय और साझेदारी स्थापित करना।

7. यहां प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर शोध और विकास करना।

8. हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में मानव सुधार से संबंधित सूचना, प्रशिक्षण और मौखिक आदान–प्रदान का बेहतर उपयोग।

9. भिवानी जिले में अधिक से अधिक रोजगार संपत्ति का निर्माण करना तथा सभी को सभ्य रूप में रोजगार की संभावनाएं प्रदान करना।

10. क्षेत्र में सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना।

11. हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए।

12. यहां ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि संबंधी योजनाओं एवं ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

13. शोध के हर क्षेत्र को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

14. अध्ययन क्षेत्र हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के सुदूर एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का प्रकाश फैलाना एवं एक अभियान के अन्तर्गत लाकर समस्त मानव जाति को प्रशिक्षित करना।

15. यहां अच्छे आकार के गुणात्मक सुधार के साथ जीवन शैली की प्रत्याशा प्रदान करना।

16. भिवानी जिले में सरकारी प्रयासों के माध्यम से प्रति व्यक्ति मुनाफा बढ़ाना।

17. क्षेत्र में पूरे वृद्धावस्था में सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना।

18. शोध क्षेत्र में बच्चियों के अधिकांश प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और स्कूलों और कॉलेजों में उनकी सुरक्षा की वारंटी प्रदान करना।

19. अनुसन्धान क्षेत्र में आवास की कम वरीयता वाले क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को दूर करना तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष :

संक्षेप में हम कह सकते है कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी बड़ी आबादी को संपत्ति के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उच्च सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण हमारा आर्थिक लक्ष्य है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उच्च आम जनता की भागीदारी और कई प्रकार की सरकारी और गैर–सरकारी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए एक अनिवार्य घटक है, वहीं दूसरी ओर यह एक जिम्मेदारी भी है। जनशक्ति एक पूँजी है, यदि इस जनशक्ति का समुचित उपयोग नहीं किया गया तो

नए कार्य हाथ नहीं लगेंगे और इस प्रकार यह संसाधनों का बोझ बन जाएगा। हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में विवेकपूर्ण नियोजन एक अत्यंत आवश्यक आवश्यकता है अन्यथा क्षेत्र का विकास अधूरा रह जाएगा।विकास का तरीका मानव–केंद्रित होना चाहिए। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य मानव की सूक्ष्मता को बढ़ाना है ताकि वह अपने विकास की संभावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके।

संदर्भ सूची :

- विश्वनाथ तिवारी एवं राम शिरोमणि पांडे, ''आर्थिक एवं मानव भूगोल'' शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी आगरा 1979।
- चतुर्भुज मां मोरिया एवं दीपक माहेश्वरी,''मानव भूगोल'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2006।
- कमलाकांत दुबे एवं महेंद्र बहादुर सिंह,''जनसंख्या भूगोल'' रावत पब्लिकेशन जयपुर 2006।
- वीएस चौहान,''मानव–आर्थिक भूगोल'' एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली।
- एसडी कोशिक,''भौगोलिक विचारधारा एवं विधि तंत्र'' रस्तोगी प्रकाशन मेरठ 1984।
- सीबी मोरिया,''मानव भूगोल'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 1985।
- एस एम जैन,''मानव एवं पर्यावरण'' साहित्य भवन आगरा 1993।
- चतुर्भुज मोरिया,''मानव भूगोल'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2000।
- बंसल,''नगरीय भूगोल'' मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2000।
- सिंह हरिहर एसटीडी,''इन अर्बन ज्योग्राफी एंड जीएसआई'' वाराणसी 1972।